SHRI VIZOL: I am known to be a man of lew words.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I associate myself with the Special Mention made by Shri Nyodek Yonggam, Member from Arunachal Pradesh, for the creation of a separate eel! for the North-East at the Centre. As well all know, the Home Ministry is burdened with heavy work and with problems all over the country. They have very little time to attend to the problems of distant regions like the Nor;h-East. We are sorry to say about it. But that is a fact of the story. Whenever things went out of order in the North-F.ast, the Home Ministry could hardly do anything but deploy the Army or police or para-military forces to deal with the situation. This has created a sense of regimentation which is alienating the people of North-East from India. In fact, North-East is reeling under the weight of military boots. So, creation of a separate cell at the Centre will relieve the pressure and lighten the burden of the Home Ministry. It will give a better access to the people of the North-East so that they can have a better chance to express themselves to the country and to the Government through this separate cell at the Centre.

With these words, I conclude my speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Thank you. Prof. Varma.

Sickness in Sandalwood-Bascd Industries due to Non-Availability of Raw Materials

प्रो.राम बक्श सिंह वर्मा(उत्तर प्रदेश)**:** धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी। महोदय,मैं इस सम्मानित सदन तथा सरकार का ध्यान एक अत्यंत विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अपने देश में चन्दन का उत्पादन मुख्य रूप से तमिलनाडु,आंध्रप्रदेश तथा कर्नाटक में होता हैं। चन्दन की लकड़ी अत्यंत कीमती होती हैं जिससे मूल्यवान मूर्तियों का निर्माण किया जाता हैं तथा चन्दन की लकड़ी से प्राप्त तेल पर आधारित विश्व प्रसिद्व ऐतिहासिक इत्र तेल का उद्योग उत्तर प्रदेश के कन्नौज नगर में सैंकड़ों वर्षो से चल रहा हैं और देश के कई अन्य प्रांतों तथा उड़ीसा आंध्रप्रदेश,कर्नाटक व तमिलनाडु आदि प्रदेशों में चन्दन की लकड़ी पर आधारित कई उद्योग चल रहे हैं जिन में इस देश के लाखें लोगों को रोजी-रोटी मिल रही हैं तथा इत्र तेल एवं अन्य पक्के माल के निर्यात से हमारे देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन हो रहा हैं। भारत में चन्दन की लकड़ी की कमी को मद्दे नजर रखते हुए सरकार ने। अप्रैल,1992 से इस के नियारत पर प्रतिबंध लगा दिया हैं जिससे कि घरेलू उद्योग हेतु पर्याप्त मात्रा में चन्दन की लकड़ी उपलब्ध हो सके। कच्चे माल के अभाव में केवल कन्नौज में 23 डिस्टीलेशन इकाइयों में से अधिकतर बंद पड़ी हैं तथा मात्र कुछ इकाइयां अत्यंत घटी हुई क्षमता पर कार्य कर रही हैं जिससे कि कन्नौज का इत्र तेल उद्योग तथा अन्य संबंधित उद्योग रूग्ण हो गए हैं। परन्तु यह आश्चर्यजनक हैं कि एक तरफ घरेलू उद्योग हेतु सरकार चन्दन की लकड़ी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पा रही हैं,वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार के पर्यावरण एंव वन मंत्रालय ने 1500 टन चन्दन की लकड़ी के निर्यात का प्रस्ताव उद्योग मंत्रालय को भेजा हैं जबकि 3 माह पूर्व 700 टन चन्दन की लकड़ी की नीलामी देसी उद्यमियों को की गयी थी,उसे आज तक पक्का नहीं किया गया हैं।

उपसभाध्यक्ष (**श्री सतीश अग्रवाल**): पीठासीन हुए अत**:** मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि निर्यातकों के माफिया गिरोह के प्रभाव में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा चन्दन की लकड़ी के निर्यात में प्रस्ताव को रद्द किया जाए एवं घरेलू व्यवसाय हेतु पर्याप्त चन्दन की लकड़ी उपलब्ध करायी जाए जिससे कि इस व्यवसाय में कार्यरत लाखों लोगों की रोजी-रोटी का सहारा बना रहे तथा चन्दन तेल से निर्मित इत्र अथवा चन्दन लकड़ी की मूर्तियों एवं अन्य पक्के माल के निर्यात से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जा सके। मैं यह भी मांग करता हूं कि 3 महीने पूर्व की गई 700 टन चन्दन की लकड़ी की नीलामी को तुरन्त पक्का कर दिया जाए ताकि संकटग्रस्त औद्योगिक इकाइयों को यथा-शीघ्र चन्दन की लकड़ी प्राप्त हो सके।

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया(**मध्य प्रदेश**): उपाध्यक्ष महोदय,मध्यप्रदेश में खूबसूरत वादियों को मारघट में

Mr. Vice-Chairman, I want to associate myself with what Prof. Varma has said since I also come from that area. It is a very historic industry and there is also a question of employment of lakhs of people. Therefore, I suggest, when the policy of the Government is not for export of sandalwood, it should be adhered to and needless auction for the purpose should not be permitted.

Danger to Environment and Decline in Ground-Water Level due to mining in Madhya Pradesh

बदला जा रहा हैं और यह बदलावट की जा रही हैं वहां के शासन की शह पर । जहां हरे-भरे वृक्ष थे,हरी-भरी वनस्पतियां थीं,बारहमासी झरने बहते थे,वहां खदान के पट्टे दे दिए गए हैं और खदान भी ऐसी कोई बड़ी कीमती वस्तु की नहीं बल्कि हुई मिट्टी की । पचासों फीट गहरे गड्ढे हुए हैं,आसपास के झरने सूखने लगे हैं,खेती के लिए जो ट्यूबवेल बने थे सिंचाई के लिए,उनका जलस्तर नीचे चला गया हैं,पीने के पानी का जलस्तर नीचे चला गया हैं और कीमती वनस्पति का विनाश वहां देखा गया हैं ।

उपसभाध्यक्ष जी,मैं आपके माध्यम से और इस महान सदन के माध्यम से वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि वह विदेशों में ही पर्यावरण सुधारने की कोशिश न करें,अपने घर में भी पर्यावरण सुधारें । मध्यप्रदेश उनका अपना प्रदेश हैं और उस प्रदेश की इतनी दुर्गति हैं कि राज्य शासन पूरी तरह से ग्रामीण पर्यावरण का विनाश करने पर उतारू हैं,जगह-जगह खदानों के पट्टे दे रखे हैं,बड़े-बड़े बगीचे,आम के बगीचे और दूसरे बगीचे,उनके नीचे वहां गड्ढे हो रहे हैं और शासन का कोई ध्यान नहीं हैं ।वहां बगीचों का विनाश हो रहा हैं,पर्यावरण का नाश हो रहा हैं । तो मैं आपके माध्यम से केन्द्र शासन से यह कहना चाहूंगा कि खुदा के वास्ते जहां खूबसूरत वादियां हैं उनको मरघट न बनवाएं, उन्हें सरसब्ज रहने दीजिए ताकि वहां का इंसान और पशु दोनों खुशहाल हो सकें ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): धन्यवाद, चनपुरिया जी । डा.बापू कालदाते । श्री पशुमपोन त.किरूट्टिनन ।

Need to open Regional Passport Office at Madurai in Tamil Nadu

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN (TAMIL NADU): Mr. Vice-Chairman, I rise to impress upon the Government the need to have u Passport Office opened at Madurai in Tamil Nadu.

Sir, there has been a persistent demand from the people of Tamil Nadu, particularly from the people of Madurai, that they should have a Regional Passport Office in Madurai City. The statistics of the Government show that the number of applications for fresh passports and for renewals is increasing year after year. The output of passport offices increased further during 1993 with the issue of over 27 lakh fresh passports. This figure represents an increase of about 21 per cent over the output in 1992 which itself was an increase of 40.4 per cent over the output for the year 1991.

So far as Tamil Nadu is concerned, there are only two Passport Offices, one at Madras and the other at Trichy. The problem of unemployment is rempant in India. Opportunities are available abundantly in other foreign countries for qualified technicians of India. Many Indians are willing to go over to foreign countries. And it would be a great service to those who are willing to go abroad if passports are made available to them without much difficulty.

When the Government is not able to solve the unemployment problem, opening of more Passport Offices and the relaxation of passport-issue rules would mitigate the hardships faced by the people. In the case of issuance of travel documents, India lags behind the West where they can be secured within a day or two. The passport offices at Trichy and at Madras, are not in a position to meet the demands of the public, particularly the Trichy Office is heavily loaded. I will give some particulars. In the Passport Office at Madras, the number of applications received in 1990 was 74,055, in 1991, the number was 1,28,130, in 1992, it was 1,41,194, in 1993, the number was 1,52,674 and in 1994, it went up to 1,88,556. In the Passport Office at Trichy, the number of applications received in 1990 was 1,32,464. In 1991, it was 2,03,805, in 1992 it was 1,81,215, in 1993, it was 2,18,491 and 1994, the number went up to 2,43,091. Both these offices are not in a position to meet the demands of the public. Not only that, the people from Kanyakumari, Tirunelveli andTuticorin districts have to come all the way to Trichy. They have to cover more than 400 kms distance. The people from Coimbatore, Nilgiris, Periyar, Salem and Dharmapuri districts have to go to Madras which is 400 kms away. So, it is beyond their reach. If the offices are located at short distances the people would be much benefited and they will not have to incur much expenditure. Just imagine the workload. I would like to know whether a single passport office can verify the applications. No. So, I wote a letter to the then External Affairs Minister, Shri Dinesh Singh, requesting him for opening a passport office at Madurai in